



Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश



संपादन

अभय सिंह

रिसर्च एसोसिएट
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

रिसर्च टीम

मनुजम पांडेय

रिसर्च एसोसिएट
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

डिजाइन

अजित कुमार सिंह



Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

**Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation**

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,



@spmrfoundation

Phone:011-69047014

विषय सूची

भूमिका

1. यूपी : उपलब्धियों के आधार पर आशीर्वाद की आकांक्षा
-डॉ दिलीप अग्निहोत्री 6
2. योगी सरकार के उपलब्धियों से भरे साढ़े चार साल - डॉ दिलीप अग्निहोत्री 9
3. योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण का आगाज
-रमेश कुमार दुबे 12
4. एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की राह पर उत्तर प्रदेश - सतीश सिंह 14
5. अयोध्या में पुनः साकार हुई त्रेता युग की दीपावली ! - नवोदित सक्तावत 17
6. केंद्र और योगी सरकार के प्रयासों से तेजी से विकसित हो रही अयोध्या
- डॉ दिलीप अग्निहोत्री 20
7. योगी राज में ग्लोबल सिटी बनने की ओर बढ़ता नोएडा - रमेश कुमार दुबे 22
8. 'सशक्त नारी, समर्थ समाज' के पथ पर अग्रसर योगी सरकार - डॉ. खुशबू गुप्ता 24
9. कृषि-औद्योगिक विकास का आधार बनेगी केन-बेतवा नदी परियोजना
- प्रमोद भार्गव 28
10. योगी राज में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे क्रांतिकारी सुधार
- डॉ दिलीप अग्निहोत्री 31
11. योगी आदित्यनाथ : कोविड काल में सुशासन का आदर्श स्थापित करने वाले
मुख्यमंत्री - प्रणय कुमार 33

12. कोरोना संकट में अपने सधे हुए क़दमों से स्थिति को नियंत्रित रखने में कामयाब योगी सरकार - नवोदित सक्तावत 36
13. योगी सरकार की उपलब्धियों से बौखलाहट में विपक्ष - नवोदित सक्तावत 39
14. यूपी : योगी राज में एक-एक कर ध्वस्त हो रहा अपराधियों का आर्थिक साम्राज्य - प्रणति तिवारी मुखर्जी 42
15. क़ानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार के मॉडल से अन्य राज्यों को लेनी चाहिए प्रेरणा - प्रणति तिवारी मुखर्जी 44

भूमिका

हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के साढ़े चार वर्ष पूरे किए हैं। बीते साढ़े चार वर्षों में राष्ट्रीय पटल पर एक नया, सक्षम और समर्थ उत्तर प्रदेश उभरकर आया है। योगी सरकार के इन साढ़े चार वर्षों में विकास के अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। पांच वर्ष पहले इसे बीमारू प्रदेश माना जाता था। निवेशकों की उत्तर प्रदेश में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों से अब यह निवेश के लिए सर्वाधिक आकर्षक प्रदेश बनकर उभरा है और उत्तम प्रदेश बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। जिस यूपी में कोई निवेशक आना नहीं चाहता था, अब वहां लोग निवेश कर रहे हैं। सरकार ने अब तक तीन लाख करोड़ से अधिक का निवेश हासिल करने में सफलता पाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की कार्ययोजना पर अमल हो रहा है। गौरतलब है कि पहले उत्तर प्रदेश में सरकारें तो बदलती थी लेकिन जन आकांक्षाएं अधूरी ही रह जाती थीं, अब स्थिति अलग है। पांच वर्ष पहले प्रदेश में बेरोजगारी दर 17 प्रतिशत थी, अब चार प्रतिशत है। पहले उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिक दंगों की चपेट में था, जबकि साढ़े चार वर्ष में प्रदेश दंगों से मुक्त है। अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल किया गया। डेढ़ हजार करोड़ रुपये से अधिक की अवैध सम्पत्ति जब्त की गई। आज प्रदेश में अपराधियों के अंदर पुलिस व कानून का भय है। एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर मिशन शक्ति तक की कोशिशों से महिलाएं सुरक्षित व सम्मानित महसूस कर रही हैं। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में चालीस लाख आवास उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगी सरकार के कोरोना आपदा प्रबंधन की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन व नीति आयोग ने की थी। किसान कल्याण की बात करें तो पूर्व की सरकारों के दौरान यूपी में किसान सरकारों की प्राथमिकता से बाहर था, लेकिन आज वह विकास के एजेंडे में शामिल है। राज्य सरकार द्वारा अब तक गन्ना किसानों को करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग छत्तीस लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, छियासठ लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत प्रदेश के 2.42 लाख किसानों को लाभ मिला है। यह उपलब्धियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम का परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव जैसे सांस्कृतिक आयोजन कर भारतीय संस्कृति को संजोने के साथ ही देश में उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में भी अग्रणी राज्य बना दिया है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ने बदलते उत्तर प्रदेश पर केंद्रित विभिन्न आलेखों को संलग्न कर इसे एक बुकलेट का स्वरूप दिया है, जिसके माध्यम से पाठक नए उत्तर प्रदेश के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं।

बृजलाल
राज्यसभा सांसद (भाजपा), पूर्व डीजीपी (उत्तर प्रदेश)

यूपी : उपलब्धियों के आधार पर आशीर्वाद की आकांक्षा

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

भाजपा की कार्यपद्धति से अनजान लोग पिछले दिनों यूपी को लेकर तरह-तरह के कयास लगाते रहे, प्रत्येक बैठक व नेताओं की यात्रा पर कहानी गढ़ते रहे। दूसरी तरफ भाजपा उत्तर प्रदेश के लिए अपने चुनावी प्रबंधन को मजबूत बनाने में लगी हुई है। इसी क्रम के अनुरूप नई दिल्ली में भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सांसद व अन्य नेता शामिल हुए।

इसमें तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ निकाली जाएगी। जेपी नड्डा ने सांसदों को मानसून सत्र के बाद अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का निर्देश दिया। कहा कि इस यात्रा के दौरान संसदीय क्षेत्र का एक भी गांव नहीं छूटना चाहिए। यात्रा के दौरान सांसद खुली जीप में घूमें, टीकाकरण अभियान और कोरोना काल में शुरू की गई योजनाओं की एक एक गांव में निगरानी करें। यह पता करें कि जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं।

सांसदों से कहा गया कि वह अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का दायित्व संभालें। बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। इसके साथ ही टीकाकरण अभियान और कोरोना काल में मोदी और राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं की प्रगति का ध्यान रखा जाएगा।

जाहिर है कि पार्टी हाईकमान को योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों पर विश्वास है। उनका आकलन है कि इन उपलब्धियों के आधार पर उत्तर प्रदेश के मतदाता भाजपा को दुबारा आशीर्वाद देंगे। सरकार की उपलब्धियां अब चर्चा में हैं।

गौर करें तो योगी सरकार ने अपने अबतक के शासन में उत्तर प्रदेश में शानदार काम किया है और उनके पास बताने के लिए उपलब्धियों की लम्बी फेहरिस्त है। पहले उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश में चौदहवें स्थान पर था, सरकार की नीतियों से आज दूसरे स्थान पर आ



गया है।

आज केन्द्र सरकार की अनेक योजनाओं में भी प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनवाये गये हैं। इसी तरह उज्ज्वला, सौभाग्य, उजाला, पीएम किसान सम्मान निधि में भी उत्तर प्रदेश ने बेहतर कार्य किया है।

पिछले चार वर्षों के दौरान प्रदेश में तीन लाख

करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाएं प्रदेश में लागू की गईं। एक लाख सत्ताईस हजार करोड़ रुपये से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। राज्य में एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी पूरी गति से संचालित किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना के सम्बन्ध में कार्य योजना

तैयार की जा रही है, वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक क्लस्टर स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही तेजी से चल रही है।

चार वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में मात्र चार एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर तथा आगरा क्रियाशील थे। पच्चीस गंतव्य स्थान हवाई सेवाओं से जुड़े थे। चार वर्ष में दो गुने अर्थात् आठ एयरपोर्ट क्रियाशील हो गए हैं, जो कुल इकहत्तर गंतव्य स्थानों पर हवाई सेवा से जुड़े हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य इस वर्ष पूर्ण कराया गया। यह एयरपोर्ट भी अब अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु तैयार है।

राज्य सरकार द्वारा चार वर्षों में चार एयरपोर्ट्स का विकास पूर्ण कराया जा चुका है। दस अन्य का विकास कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चार वर्ष पहले बारह मेडिकल कॉलेज थे। अब उनकी संख्या लगभग चार गुनी बढ़ गई है।

प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में चालीस लाख आवास उपलब्ध कराए गए हैं। करीब ढाई करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया गया है। चौवन लाख कामगार श्रमिक, स्ट्रीट वेण्डर्स आदि को भरण पोषण भत्ते का लाभ मिला। पन्द्रह करोड़ गरीब परिवारों को कोरोना काल में निःशुल्क राशन प्रदान किया गया।

एक करोड़ अड़तीस लाख घरों में निःशुल्क

बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। सत्तासी लाख से अधिक लोगों को वृद्धावस्था महिला व दिव्यांगजन पेंशन दी गई है। हर घर नल योजना के तहत तीस हजार ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल योजना लागू की गई है।

हर जिला मुख्यालय को फोर लेन से तथा तहसील मुख्यालयों और विकास खण्ड मुख्यालयों को दो लेन से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ-साथ प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण और उत्तर प्रदेश में इण्डस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है।

इन सबके अलावा कानून व्यवस्था के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने मिसाल कायम की है। अपराधियों में पुलिस का भय व्याप्त हो रहा है। बाहुबलियों पर शिकंजा कसा गया है। दंगा और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नज़ीर भी उत्तर प्रदेश ने पेश की है।

कुल मिलाकर इन तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के विकास और चाक-चौबंद कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धतापूर्वक काम कर रही है। योगी सरकार के इन कार्यों को देखते हुए चुनाव में उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद की पूरी-पूरी संभावना है।

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

योगी सरकार के उपलब्धियों से भरे साढ़े चार साल

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

बी ते दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साढ़े चार वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। योगी सरकार के इन साढ़े चार वर्षों में विकास अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। पांच वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश की राजनीति सपा और बसपा में सिमटी थी। एक पार्टी से मतदाता नाराज हुए तो दूसरी पार्टी को ले आये। उससे नाराज हुए तो फिर बदलाव कर दिया। सरकारें बदलती थीं लेकिन व्यवस्था में बदलाव नहीं होता था। जन आकांक्षाएं अधूरी ही रह जाती थीं।

आज से साढ़े चार वर्ष पहले मतदाताओं ने विकल्प के रूप में भाजपा को मौका दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते थे कि केवल सरकार का बदलना पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले व्यवस्था में बदलाव व सुधार किया। निवेश व विकास के अनुकूल माहौल बनाया गया। इसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। बयालीस विकास योजनाओं में उत्तर प्रदेश नम्बर वन पर है। कई योजनाओं में योगी सरकार की उपलब्धि सत्तर वर्षों पर भारी है। सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए योगी

सरकार की ओर से तीन प्रकार की बुकलेट जारी की गई हैं। एक बुकलेट सोलह, दूसरी बावन और तीसरी सिर्फ चार पेज की है। मतलब गागर में सागर। पहली बुकलेट में पारदर्शी और जवादेह सरकार का दस्तावेज है। विकास के कीर्तिमान का उल्लेख है। इसके कवर पेज पर वैचारिक प्रतिबद्धता की झलक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभु श्रीराम की प्रतिमा भेंट कर रहे हैं। दूसरी बुकलेट में 'विकास की लहर, हर गांव-हर शहर' की दास्तान है। 'काम दमदार योगी सरकार' के नारे के साथ चतुर्मुखी विकास का संदेश है। तीसरी बुकलेट में 'सोच ईमानदार-काम दमदार, छा गयी योगी सरकार' का जज्बा है। यह संकल्प से सिद्धि की यात्रा है।

वस्तुतः साढ़े चार वर्षों में राष्ट्रीय पटल पर एक नया, सक्षम और समर्थ उत्तर प्रदेश उभर कर आया है। पांच वर्ष पहले इसे बीमारू प्रदेश माना जाता था। निवेशकों की उत्तर प्रदेश में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जबकि मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों से यह निवेश के लिए सर्वाधिक आकर्षक प्रदेश बन गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर मिशन शक्ति तक की कोशिशों से

महिलाएं सुरक्षित व सम्मानित महसूस कर रही हैं।
स्वावलम्बन की मिसाल बन रही हैं।

पांच वर्ष पहले प्रदेश में बेरोजगारी दर सत्रह प्रतिशत थी। अब चार प्रतिशत है। योगी के कोरोना आपदा प्रबंधन की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन व नीति आयोग ने भी की है। पहले उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिक दंगों की चपेट में था, जबकि साढ़े चार वर्ष में प्रदेश दंगों से मुक्त होने की राह पर बढ़ा है। अपराधियों माफिया के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल किया गया। डेढ़ हजार करोड़ रुपये से अधिक की अवैध सम्पत्ति जब्त की गई।

इन्वेस्टर्स समिट पहले भी होती थी, लेकिन सुरक्षित माहौल के अभाव में उद्योगपति निवेश को उत्सुक नहीं थे। अब कानून व्यवस्था बेहतर होने से प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। योगी सरकार ने साढ़े चार साल में प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ाने का रास्ता बना दिया है। यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।

उद्योगों के लिए माहौल बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप जिस यूपी में कोई निवेशक आना नहीं चाहता था, अब वहां लोग निवेश कर रहे हैं। सरकार ने अब तक तीन लाख करोड़ से अधिक का निवेश हासिल करने में सफलता पाई है। इसी का परिणाम है कि यूपी में प्रतिव्यक्ति आय दोगुनी से अधिक पहुंच गई है।

चार-पांच साल पहले तक यूपी में किसान सरकारों की प्राथमिकता से बाहर था, लेकिन आज वह राजनीति के एजेंडे में शामिल है। किसानों के उत्थान के लिए, उनकी आय में दोगुना वृद्धि के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। सरकार ने दो करोड़ इकसठ लाख शौचालय बनाकर तैयार किए जिसका लाभ दस करोड़ लोगों को मिला है। जिला मुख्यालयों में दस घंटे बिजली और तहसील मुख्यालय पर बाइस घंटे बिजली की सुविधा दी जा रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अठारह घंटे बिजली पहुंचाने का काम सरकार कर रही है।

इसके अतिरिक्त योगी सरकार द्वारा किसान व गरीब कल्याण, लाखों करोड़ के निवेश, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार, पांच एक्सप्रेस वे पर कार्य, स्वास्थ्य आदि तमाम और क्षेत्रों में भी पिछली सरकारों के रिकार्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। जबकि पिछला करीब दो वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित रहा है। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने विकास की गति कम नहीं होने दी। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की कार्ययोजना पर अमल चल रहा है। राज्य सरकार की कार्यपद्धति में बदलाव से आय भी बढ़ी है। शीघ्र ही स्टेट जीएसटी से होने वाली आय एक लाख करोड़ रुपये की सीमा को पार कर लेगी। राज्य सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का

भुगतान कराया है।

कोरोना काल में भी सभी एक सौ उन्नीस चीनी मिलें संचालित की गईं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग छत्तीस लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। छियासठ लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है तथा किसानों को ग्यारह हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मक्के की खरीद कर किसानों को करीब दो सौ करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत प्रदेश के दो करोड़ बयालीस लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके लिए राज्य को भारत सरकार से प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में चालीस लाख आवास उपलब्ध कराए गए हैं। चौवन लाख कामगार श्रमिक, स्ट्रीट वेण्डर्स आदि को भरण-पोषण भत्ते का लाभ मिला है। कामगारों श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग का गठन किया गया है। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संचालित की जा रही है।

साढ़े चार वर्ष पहले उत्तर प्रदेश 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में देश में चौदाहवें स्थान पर था, आज

व्यापार का वातावरण बना है और प्रदेश देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में दूसरे स्थान पर आ गया है। आज प्रदेश में तेजी के साथ निजी निवेश हो रहा है। निजी क्षेत्र में अब तक तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। इसके माध्यम से पैंतीस लाख युवाओं को रोजगार व नौकरी के साथ जोड़ा गया है।

जीएसटी के तहत उनचास हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था, जो अब बढ़कर एक लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं आबकारी के रूप में चार वर्ष पहले करीब बारह हजार करोड़ रुपए राजस्व मिलता था, जो कि अब छत्तीस हजार करोड़ रुपए मिल रहा है। स्टाम्प एवं निबंधन में नौ से दस हजार करोड़ रुपए मिलता था, जो कि अब पच्चीस हजार करोड़ हो गया है। मंडी शुल्क में छह से आठ सौ करोड़ रुपए मिलता था, अब दो हजार करोड़ रुपए प्राप्त होता है। इसी प्रकार पूर्व में माइनिंग से उत्तर प्रदेश को करीब तेरह सौ करोड़ रुपए की आय ही होती थी, जो अब बढ़कर बयालीस सौ करोड़ रुपये तक पहुँच गयी है। यह सब उपलब्धियां योगी सरकार के चुस्त प्रशासन, सही नीयत तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश का ही परिणाम हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी के सुशासन से उत्तर प्रदेश न केवल विकास के पथ पर आगे बढ़ा है बल्कि यहाँ 'ईज आफ लिविंग' भी बेहतर हुई है।

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण का आगाज

रमेश कुमार दुबे

1

1990 के दशक में जब दक्षिण व पश्चिम भारत के राज्य सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे नवोन्मेषी उद्यमों की नींव रख रहे थे तब उत्तर भारत के राज्य जातिवादी राजनीति की आग में हाथ सेंक रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर भारत के राज्य विकसित क्षेत्रों के लिए कुशल-अकुशल मजदूरों की आपूर्ति करने लगे।

उत्तर प्रदेश की कहानी इससे अलग नहीं रही। जैसे-जैसे जाति व धर्म की राजनीति ने जोर पकड़ा वैसे-वैसे कानून का राज कम होता गया। कानून का राज न होने से गुंडाराज व माफियाराज पनपा। माफियावाद के पेड़ की छांव में नये उद्योग तो नहीं लगे जो उद्योग धंधे थे वे भी बंद होते गए।

योगी सरकार ने कानून का राज कायम किया जिससे लंबे अरसे बाद प्रदेश में विकास की राजनीति शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज व गुंडाराज के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जिससे प्रदेश में विश्वास का वातावरण बना। इसी का नतीजा है कि देशी-विदेशी निवेशक उत्तर प्रदेश को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं।

2017 में जब योगी सरकार ने सत्ता संभाली थी तब उत्तर प्रदेश प्रदेश व्यापार सुगमता सूचकांक में 14 वें पायदान पर था। अब उत्तर प्रदेश व्यापार सुगमता सूचकांक में पहले पायदान पर है। निवेश मित्र नीतियों और कानून का राज कायम होने का ही नतीजा है कि 2020-21 में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। मेट्रो रेल व एक्सप्रेस वे सहित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और बिजली की स्थिति में सुधार लाकर उत्तर प्रदेश की उत्पादक क्षमता में वृद्धि की गई है।

योगी सरकार प्रदेश के औद्योगीकरण की ओर ध्यान देते हुए शहरों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रही है। सरकार ने राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार की योजना महोबा, लखनऊ, ललितपुर और रामपुर में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की है।

ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास अलीगढ़ में भी औद्योगिक क्षेत्र

की स्थापना की जाएगी। सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा और गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क बना रही है खुर्जा में पाटरी कांप्लेक्स भी विकसित करने की योजना है। एक जिला एक उत्पाद के तहत खुर्जा की पाटरी को शामिल किए जाने के बाद से इसकी मांग में बढ़ोत्तरी हुई है।

मेक इन इंडिया मुहिम के तहत देश को रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पांच हजार हेक्टेयर भूमि पर रक्षा उद्योग गलियारे को विकसित किया जा रहा है। यहां बड़े पैमाने पर बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, मिसाइल, बंदूकें आदि बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना कर रही है।

कभी पूरब का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर शहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से एक बार फिर विश्व के मानचित्र पर एक औद्योगिक शहर के रूप में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। यहां के रमईपुर गांव में 235 एकड़ में मेगा लेदर पार्क बनाया जा रहा है। यह देश का पहला मेगा लेदर पार्क होगा जहां उत्पादन, उत्पादों के प्रदर्शन, खरीदारों को ठहरने आदि सभी तरह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

नोएडा में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल

सिटी बन रही है। उत्तर प्रदेश को गारमेंटिंग हब बनाने के लिए पांच एपेरल-गारमेंटिंग पार्कों की स्थापना की जा रही है।

योगी सरकार बड़े उद्योगों के साथ-साथ प्रदेश के गांवों व कस्बों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इसके लिए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से लोगों को न्यूनतम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, मछली पालन, आटा चक्की, कोल्ड रूम, हर्बल उत्पाद, दाल तथा धान प्रसंस्करण यूनिट लगाने के लिए सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने की योजना है।

योजना के तहत हाथ कागज उद्योग, रेशा उद्योग, वन आधारित उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी व ग्रामीण यांत्रिकी उद्योग और अन्य सेवा संबंधी उद्योग स्थापित करने के लिए भी कर्ज दिलाया जाएगा।

समग्रतः उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति शुरू होने से जाति की राजनीति करने वाले नेताओं की जमीन खिसकने लगी। यही कारण है कि ये नेता एक बार फिर प्रदेश को जातिवादी राजनीति की आग में झोंकने की कवायद में जुट गए हैं लेकिन अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है।

*(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में
अधिकारी हैं। वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत
विचार उनके निजी हैं।)*

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की राह पर उत्तर प्रदेश

सतीश सिंह

मो दी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। इस संकल्पना को साकार करने के लिये सभी राज्यों की सहभागिता जरूरी है। मामले में उत्तरप्रदेश सरकार ने अग्रतर कदम उठाते हुए उत्तरप्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने की संकल्पना जाहिर की है। उत्तरप्रदेश की मौजूदा अर्थव्यवस्था लगभग 230 बिलियन डॉलर की है। राज्य की जीडीपी में कृषि का हिस्सा 27 प्रतिशत, इंडस्ट्री का हिस्सा 26 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का हिस्सा 47 प्रतिशत है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की है।

अगर योगी सरकार उत्तरप्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की बनाने में सफल होती है तो मोदी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की बनाने में आसानी से सफल हो सकती है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की बनाने में मशक्कत करने की जरूरत है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में देश की आबादी के करीब 17 प्रतिशत लोग निवास करते हैं, लेकिन जीडीपी में इसका हिस्सा 8 प्रतिशत है। अगर सरकार सभी युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था करती है तो जीडीपी में उत्तरप्रदेश का योगदान बढ़ सकता है। सेवा क्षेत्र में, जीएसवीए को 2019-20 के दौरान 7.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

सेवा क्षेत्र यह अनुमान विगत 3 सालों के औसत पर आधारित है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मौजूदा कीमतों पर उत्तरप्रदेश का जीएसडीपी 17.95 ट्रिलियन रुपये के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। इस आंकड़ा से पता चलता है इस क्षेत्र को सशक्त करने की अभी अपार संभावनाएं हैं। इसलिए, योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में युवाओं के विकास और रोजगार व स्व-रोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया है।

सरकार ने प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार युवा, जो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, के लिए एक प्रशिक्षुता योजना शुरू की है। इसके तहत हर युवा को एक उद्यम से जोड़ा जाएगा और सरकार उसे वित्तीय सहायता देगी। इसके अलावा योगी सरकार युवाओं के कौशल

विकास पर भी ध्यान दे रही है, ताकि युवा स्व-रोजगार की मदद से आत्मनिर्भर बन सकें।

योगी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये क्षेत्रवार अल्पकालीन और दीर्घकालीन रणनीति बनाई है। सरकार सुशासन को बेहतर करने, कारोबारी निर्णय में तेजी लाने, कारोबारी सुगमता को बढ़ाने, मौजूदा नियमों का सुचारु क्रियान्वयन आदि करने की कोशिश कर रही है। राज्य में सबसे अहम क्षेत्र कृषि, उद्योग और सेवा हैं। इसलिए, सरकार इन क्षेत्रों को सबसे पहले मजबूत करना चाहती है। इसके लिये कुछ उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं, जो समय-समय पर इस दिशा में बेहतरी लाने के लिये सुझाव दे रही हैं।

कारोबारी सुगमता के मामले में प्रदेश की स्थिति

में काफी सुधार हुआ है, लेकिन योगी सरकार औद्योगिक क्लस्टरों के विकास के साथ-साथ कारोबारी सुगमता को और बढ़ाना चाहती है, ताकि प्रदेश में कारोबारी नये-नये उद्योग शुरू कर सकें और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आये।

भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, बेंगलुरु और अर्नेस्ट यंग के अनुसार योगी सरकार के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में 70 प्रतिशत भूमिका योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से जुड़ी है। अस्तु, सरकार सुशासन को बेहतर करने, इंस्पेक्टर राज को खत्म करने, परमिट लेने की प्रक्रिया को आसान करने आदि पर काम कर रही है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने वित्त वर्ष 2018-19 में 1.14 ट्रिलियन रुपये के कुल निर्यात

में लगभग 80 प्रतिशत का योगदान दिया था। इसलिए, नई निर्यात नीति में इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य के औद्योगिक उत्पादन में इस क्षेत्र का 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तरप्रदेश में वित्त वर्ष 2015-16 में एमएसएमई इकाइयों की संख्या 4.4 मिलियन थी, जो वित्त वर्ष 2017-18 में बढ़कर 9 मिलियन इकाइयां हो गईं।

वित्त वर्ष 2017-18 में राज्य में 9



मिलियन एमएसएमई इकाई सक्रिय थीं, जिनके वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 14 मिलियन होने का अनुमान है। इस तरह, इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। योगी सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) से उत्तरप्रदेश की प्रमुख वन-डिस्ट्रिक्ट-वन-प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना को सफल बनाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा ऋण देने के लिये कहा है। माना जा रहा है कि इस योजना की मदद से स्वदेशी उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी।

योगी सरकार ने सितंबर में पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कृषि आय को बढ़ाने और कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। सरकार की यह नीति कृषि निर्यात के लिए संस्थागत तंत्र बनाने, निर्यात उन्मुख वस्तुओं को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल पर्यावरणीय किस्मों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।

नई कृषि-निर्यात नीति की मदद से, राज्य को अगले पांच वर्षों में कृषि वस्तुओं के शिपमेंट का मूल्य \$ 2,524 मिलियन या 17,591 करोड़ रुपये से दोगुना होने की उम्मीद है। कृषि-निर्यात नीति की मदद से योगी सरकार 50 हेक्टेयर भूमि पर निर्यात-उन्मुख फसलों की खेती को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देगी, जिसका 40 प्रतिशत हिस्सा पहले वर्ष में दिया जायेगा।

योगी सरकार आधारभूत संरचना को भी मजबूत करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। इस आलोक में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का कार्य जल्द पूरा किया जायेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे को भी यथाशीघ्र मूर्त रूप देने की कोशिश की जायेगी।

योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इस चौथे बजट में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें नए विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज खोलना भी शामिल है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिये प्रदेश में अनेक मेडिकल कॉलेज भी खोले जायेंगे। सरकार की कोशिश निवेश में वृद्धि की भी है। इस आलोक में डिफेंस एक्सपो 2020 में राज्य को 50,000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।

कहा जा सकता है कि योगी सरकार की कोशिशों से उत्तरप्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि योगी सरकार जरूरी क्षेत्रों यथा, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

अयोध्या में पुनः साकार हुई त्रेता युग की दीपावली !

नवोदित सक्तावत

मो इस दीपावली अयोध्या नगरी के पूरे नगरवासियों ने कुछ ऐसा देखा जिसकी अभी तक कल्पना भी नहीं रही होगी। दीपोत्सव का पर्व यादगार बन गया। मानो साक्षात् त्रेता युग इस युग में उतर आया हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अयोध्या में दीपावली पर्व भव्य पैमाने पर मनायी गयी। इस आयोजन की सूत्रधार भले ही सरकार थी, लेकिन यह जन जन का पर्व था और इसमें नगर का प्रत्येक नागरिक सम्मिलित हुआ। अयोध्या नगरी एक ऐसे विराट आयोजन की साक्षी बनी जिसका जिक्र बरसों तक किया जाता रहेगा।

त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान श्रीराम रावण वध करके अयोध्या नगरी लौटे थे, ठीक उसी प्रकार इस आयोजन में भी राम जी का आगमन मंचित किया गया और पावन सरयू नदी के तट पर दीपों की विशाल कतार से प्रकाश करके स्वागत किया गया। यह कोई साधारण दीप-पर्व नहीं था, इसमें डेढ़ लाख से अधिक दीये जलाए गए जिनसे सरयू के घाट जगमगा उठे। यह पूरी तरह से एक सुनियोजित एवं व्यापक पैमाने पर संचालित कार्यक्रम था जो कि पूरे देश के आकर्षण का केंद्र बना।

इस आयोजन के बहाने यहां यह बात करना जरूरी है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस प्रकार के आयोजन की क्या आवश्यकता पड़ गई। इसके कुछ कारण हैं। वास्तव में, अयोध्या नगरी की पहचान पूरे विश्व पटल में भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में ही है। निश्चित ही अयोध्या में प्रतिवर्ष और पूरे साल भर श्रीराम से संबंधित आयोजनों की श्रृंखला संचालित होती रहना चाहिये, लेकिन अबसे पूर्व ऐसा नहीं था। इस धार्मिक नगरी के साथ आक्रांता बाबर का भी नाम जोड़ दिया गया और अनावश्यक रूप से बाबरी मस्जिद का जिक्र जब-तब कर दिया जाता है। इससे इस पवित्र नगरी का महत्व क्षीण होता जाता है।

इस मामले में हमें योगी आदित्यनाथ के पुरुषार्थ, साहस और पहल की मुक्त कंठ से सराहना करना होगी कि सत्ता संभालने के बहुत कम समय में ही उन्होंने अयोध्या में दीपावली पर्व विराट स्तर पर मनाने जैसे बड़े आयोजन का बीड़ा उठाया और उसे साकार भी कर दिखाया। कहना न होगा कि दीप पर्व के दूसरे दिन यानी रूप चतुर्दशी के दिन हुए इस आयोजन पर सुबह से देश भर की निगाहें थीं। विभिन्न

सूचना-संचार माध्यमों से जनता को पूरे कार्यक्रम की जानकारी लगातार मिलती रही। उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी ने भी इस महती आयोजन में श्रेष्ठ क्रियान्वयन कर दिखाया।

पूरे अयोध्या नगर में सुबह से दीपावली पर्व को लेकर उत्साह था। महिलाएं सड़कों पर रंगोली बना रही थीं, पुरुष स्वागत द्वार की सजावट में रत थे। नगर के एक कॉलेज से श्रीराम के जीवन प्रसंग पर आधारित झांकियां निकाली गईं जिन्होंने मन मोह लिया। श्रीराम, लक्ष्मण एवं सीता जी का रूप धरे कलाकारों को लेकर पुष्पक विमान के रूप में हेलीकाप्टर शाम 4 बजे रामकथा पार्क पर उतरा। यहां

मुख्यमंत्री योगी ने स्वयं राम, लक्ष्मण एवं सीता का आरती उतारकर स्वागत किया। इस दौरान आकाश से पुष्पवर्षा भी हुई। शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच पूरा वातावरण पावन हो गया।

शाम के समय सरयू के तट पर लाखों की संख्या में दीये जलाए गए और पूरा दृश्य दैदीप्यमान हो उठा। नगर की धर्मप्राण जनता को संबोधित करते हुए योगी ने स्पष्ट संकेत दिया कि अयोध्या के लोगों का सपना पूरा किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि रामराज्य की जो अवधारणा त्रेतायुग में थी, उसी के निहितार्थ को वर्तमान युग में लागू करते हुए समाज के लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।



योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों को आड़े हाथों भी लिया और कहा कि जिस प्रकार भगवान श्रीराम ने राक्षसी शक्तियों का नाश किया था, उसी प्रकार वर्तमान संदर्भ में प्रदेश में व्याप्त बुराइयों जैसे परिवारवाद, जातिवाद का विनाश हो चुका है।

इससे पहले योगी ने 133 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया और अयोध्या नगरी को विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में मुहर लगाई। राम कथा पार्क में आयोजित की गई रामलीला में इंडोनेशिया के कलाकारों ने अभिनय प्रस्तुत किया। इस प्रकार यह आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन बन पड़ा।

इस प्रकार खास थी अयोध्या की यह दीपावली
स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार अयोध्या में भव्य दीपावली मनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही अधिकारीगण स्थल निरीक्षण पर पहुंचे थे। उन्होंने संतों, महंतों से क्रमवार विमर्श किया और आयोजन की रूपरेखा रखी। योजना में नगर के प्रमुख देवस्थलों एवं सरयू के घाटों को सजाना शामिल किया गया था। प्रत्येक मंदिर का शिखर रोशनी से नहाया। राम की पैड़ी, कनक भवन, हनुमानगढ़ी जैसे प्रमुख मंदिरों पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। मिट्टी के बनाए गए दीपकों का प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया गया। यह आयोजन अपने आप में अनूठा आयोजन बनकर उभरा।

सरयू के तट पर बना दीयों का नया कीर्तिमान

इस विराट दीपोत्सव में सरयू नदी के तट पर नया कीर्तिमान कायम किया गया। यहां 1 लाख 87 हजार दीये प्रज्ज्वलित किए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधिकारिक दल ने स्वयं यहां रहकर पूरे आयोजन का मुआयना किया। दल ने ड्रोन कैमरों से दीयों की संख्या, प्रज्ज्वलन और संसाधनों की उपलब्ध की लगातार जांच की। इसके बाद इस नए कीर्तिमान का बुक में दर्ज होना लगभग तय हो गया है।

ऐसा आयोजन समय की मांग

अयोध्या की विराट दीपावली वास्तविकता में समय की मांग थी। लंबे समय से यहां ऐसे किसी आयोजन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो कि देश सहित दुनिया को हिंदू धर्म एवं धार्मिक आख्यानों की श्रेष्ठता का संदेश दे। पूर्ववर्ती शासन के समय यह नगर सांप्रदायिक ताकतों के हवाले कर दिया गया था, जहां केवल दंगा फसाद ही सुनने, देखने में आता था। निश्चित ही योगी आदित्यनाथ को इसका श्रेय दिया जाना चाहिये कि उन्होंने इतना भव्य और सुंदर आयोजन करके सृजनात्मकता का भी संदेश दिया और संकेत स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतन्त्रता वाले इस देश में किसी भी कीमत पर धार्मिक मूल्यों का हनन नहीं होने दिया जाएगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके

निजी विचार हैं।)

केंद्र और योगी सरकार के प्रयासों से तेजी से विकसित हो रही अयोध्या

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

ती र्थाटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व रहा है। यहां के अनेक स्थल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रहे हैं। लेकिन विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं की ओर पहले अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। योगी आदित्यनाथ इस कमी को दूर कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पहले की सरकारें अयोध्या का नाम लेने से बचती थी। इस कारण यहां पर्याप्त विकास नहीं किया गया।

इसी प्रकार श्री कृष्ण जन्म स्थली मथुरा वृंदावन व भोलेनाथ की नगरी काशी की भी प्रतिष्ठा है। काशी तो दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन नगरी है। योगी सरकार इस सभी स्थलों का गरिमा के अनुकूल विकास कर रही है।

मुख्यमंत्री लगभग दो दर्जन बार अयोध्या की यात्रा पर आ चुके हैं। प्रत्येक बार वह यहां के लिए विकास की कोई ना कोई योजना भी लाते रहे हैं। इसके अलावा पहले से चल रही योजनाओं की समीक्षा भी करते हैं। ऐसे स्थलों का समग्र विकास किया जा रहा है जिससे विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी सकारात्मक संदेश मिले।

बीते रोज मुख्यमंत्री योगी पुनः अयोध्या पहुँचे

जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास तथा सुग्रीव किला पीठाधीश्वर जगतगुरु विश्वप्रपन्नाचार्य से भी मिले। साथ ही, उन्होंने राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न वॉर्डों में जाकर मरीजों से संवाद किया। उनके स्वास्थ्य व यहां मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का अधिकारियों को निर्देश दिया।

समग्र विकास में दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शामिल है। यहां लोगों का इलाज भी हो रहा है। मेडिकल विद्यार्थियों की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। इस मेडिकल कॉलेज को और सुविधा जनक बनाने के लिए अनेक निर्माण कार्य चल रहे हैं। कई निर्माण कार्य पूरे होने वाले हैं।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से मास्टर प्लान में शामिल बीस हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी। उस वर्चुअल समीक्षा में योगी आदित्यनाथ व संबंधित अधिकारी शामिल हुए थे। मास्टर प्लान में सभी विकास परियोजनाओं

को शामिल किया गया है। इसमें पुरातत्व महत्व के मंदिरों और परिसरों का जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण शामिल है।

बीस हजार करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट में क्रूज पर्यटन परियोजना, रामकी पैड़ी पुनर्जनन परियोजना, रामायण आध्यात्मिक वन, सरयू नदी आइकॉनिक ब्रिज, प्रतिष्ठित संरचना का विकास, पर्यटन सर्किट का विकास, ब्रांडिंग अयोध्या, चौरासी कोसी परिक्रमा के भीतर दो सौ आठ विरासत परिसरों का जीर्णोद्धार, सरयू उत्तर किनारे का विकास आदि शामिल हैं।

इसके साथ ही अयोध्या को आधुनिक स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। सरकार ने सैकड़ों पर्यटकों के सुझाव के बाद एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। अयोध्या के विकास की परिकल्पना एक आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन हब और एक स्थायी स्मार्ट सिटी के रूप में की जा रही है। कनेक्टिविटी में सुधार के प्रयास जारी है। इनमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के विस्तार, बस स्टेशन, सड़कों और राजमार्गों व ढांचा परियोजनाओं का निर्माण शामिल है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप भी प्रस्तावित है।

इसमें तीर्थयात्रियों के ठहरने की सुविधा, आश्रमों के लिए जगह, मठ, होटल, विभिन्न राज्यों के भवन आदि शामिल हैं। अयोध्या में पर्यटक सुविधा केंद्र व विश्व स्तरीय संग्रहालय भी बनाया जाएगा। सरयू के

घाटों के आसपास बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास होगा। सरयू नदी पर क्रूज संचालन भी शुरू होगा। ग्रीनफील्ड सिटी योजना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरयू तट पट विकास, पैसठ किमी लंबी रिंग रोड, पर्यटन केंद्र, पंचकोसी परिक्रमा विकास मार्ग आदि से अयोध्या की तस्वीर बदल जाएगी।

इसमें कोई संदेह नहीं कि 2014 से पहले तक अयोध्या उपेक्षित थी। यह विश्व स्तरीय पर्यटन व तीर्थाटन केंद्र रहा है। लेकिन यहां स्थानीय स्तर की भी सुविधाएं नहीं थी। फिर भी आस्था के कारण करोड़ों लोग यहां परेशानी उठाकर भी आते थे। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। इसको स्मार्ट व विश्व स्तरीय नगर बनाने का कार्य प्रगति पर है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या आने वाले समय में वैश्विक मानचित्र में एक नया स्थान बनाने जा रहा है। अयोध्या विश्वस्तरीय पर्यटन केन्द्र के साथ-साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक बड़ा केन्द्र बनाया जाएगा। अयोध्या में इन सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं।

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

योगी राज में ग्लोबल सिटी बनने की ओर बढ़ता नोएडा

रमेश कुमार दुबे

जिस नोएडा के बारे में यह अंधविश्वास रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है वही नोएडा आज देश का सबसे अधिक निवेश आकर्षित करने वाला क्षेत्र बन चुका है। नोएडा में पिछले साढ़े चार वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ 64,362 करोड़ रुपये का निवेश आया है। इस निवेश से नोएडा में 4,84,922 लोगों को रोजगार मिला।

यदि देश के सभी 718 जिलों को देखें तो किसी भी जिले में इतना अधिक निवेश नहीं आया है। इस प्रकार मुंबई, बंगलोर जैसे दिग्गज शहरों को पीछे छोड़ते हुए नोएडा सबसे अधिक औद्योगिक निवेश वाला क्षेत्र बन गया है। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बार-बार नोएडा आने और अरबों की योजनाओं के उद्घाटन-शुभारंभ के कारण हासिल हुई है।

उल्लेखनीय है कि पिछले 30 साल से इस तरह का अंधविश्वास फैलाया जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नोएडा आना अशुभ है। यही कारण है कि कोई मुख्यमंत्री नोएडा आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव केवल

एकबार नोएडा आ सके।

चौड़ी और चमचमाती सड़कें, हरे-भरे पार्क, ट्रैफिक को रफ्तार देते अंडरपास आज नोएडा की पहचान बन चुके हैं। नोएडा में तीन औद्योगिक विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं। नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी।

इन तीनों औद्योगिक प्राधिकरणों ने पिछले डेढ़ वर्षों में देशी-विदेशी निवेशकों को 3188 भूखंड बेचा है। इन निवेशकों ने 64,362 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इनमें सैमसंग, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, अडानी ग्रुप, केंट आरओ और हल्दीराम जैसे बड़े निवेशक शामिल हैं।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश सरकार की लॉजिस्टिक नीति के तहत ग्रेटर नोएडा में 7725 करोड़ रुपये के निवेश से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बन रहा है।

तेजी से विकास कर रहा है। एमएसएमई पार्क, एपारल पार्क, टॉय सिटी, मेडिकल पार्क, फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट यमुना प्राधिकरण में स्थापित हो रहे हैं। अब सरकार 100 एकड़ में प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क बना रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों से प्रभावित होकर देश-विदेश के बड़े निवेशक नोएडा में निवेश कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट में साइन हुए कुल एमओयू में करीब 60 प्रतिशत नोएडा जिले के लिए हुए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की लॉजिस्टिक नीति के तहत ग्रेटर नोएडा में 7725 करोड़ रुपये के निवेश से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बन रहा है। ग्रेटर नोएडा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कौशल विकास केंद्र खुल रहा है। मुंबई की भांति यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में फाइनेंस सिटी की स्थापना हो रही है।

इस फाइनेंस सिटी में देश भर की वित्तीय संस्थाओं को प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा। फिल्म सिटी में देश के सभी बैंकों के कार्पोरेट दफ्तर, वित्तीय संस्थाएं, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी बाजार से जुड़े कार्यालय आदि को जमीन दी जाएगी। यहां पर इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा।

जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नोएडा ही नहीं समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नया आयाम देगा। इससे नोएडा के

चौड़ी और चमचमाती सड़कें, हरे-भरे पार्क, ट्रैफिक को रफ्तार देते अंडरपास आज नोएडा की पहचान बन चुके हैं। नोएडा में तीन औद्योगिक विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं। नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी।

ग्लोबल एक्सपोजर में सहायता मिलेगी। गौरतलब है कि बहुआयामी प्रगति के लिए जो भूमिका कभी बंदरगाह वाले तटीय क्षेत्रों की होती थी वही आज हवाई क्षेत्र की हो चुकी है। यही कारण है कि योगी सरकार इस एयरपोर्ट को प्राथमिकता दे रही है।

नोएडा में जिस तरह एक नई इलेक्ट्रानिक सिटी बन रही है उसे इस एयरपोर्ट से काफी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं प्रस्तावित फिल्म सिटी के विकास में भी यह एयरपोर्ट अहम भूमिका निभाएगा। समग्रतः दशकों तक जातिवादी राजनीति में उलझे उत्तर प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। नोएडा इसकी बानगी भर है।

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं। वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

‘सशक्त नारी, समर्थ समाज’ के पथ पर अग्रसर योगी सरकार

डॉ. खुशबू गुप्ता

वर्तमान में कोरोना महामारी ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संकट के साथ-साथ सम्पूर्ण मानवता के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। इसने न केवल गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता को जन्म दिया है बल्कि सरकारों को आधारभूत संरचनात्मक ढांचे में व्यापक सुधार और परिवर्तन करने पर भी विवश किया है।

सरकारें समय की आवश्यकता को केंद्र में रखकर नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक नियोजन पर बल भी दे रही हैं। जहाँ सरकार के समक्ष इस वैश्विक महामारी ने चुनौती उत्पन्न की है, वहीं सरकारें इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने का कार्य भी कर रही हैं।

गौरतलब है कि समाज के विकास की प्रक्रिया में देश की आधी आबादी की महती भूमिका होती है। नारी की महत्ता को केंद्र में रखकर उन्हें सशक्त बनाने हेतु लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत कानून, विकासात्मक नीतियों का निर्माण, विभिन्न योजनायें, कार्यक्रम जैसी पहले की जाती रही हैं। इसी सन्दर्भ में यदि हम वर्तमान संकट के समय महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार की

योजनाओं, नीतिओं, कार्यक्रमों की बात करे तो केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।

आज महिलाएं कोरोना की नई योद्धा के रूप में अपना योगदान कर रही हैं। जहाँ एक तरफ महामारी से प्रवासी श्रमिक तथा स्थानीय क्षेत्रों के लोग बहुत व्यापक रूप से बेरोजगारी, गरीबी के शिकार हो रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो योगी सरकार ने इस गंभीर समस्या को अवसर के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है।

स्वावलंबी और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए योगी सरकार द्वारा एमएसएमई तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के सम्बन्ध में नीतियों में संशोधन के लिए कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से “हर हाथ को काम हर घर को रोजगार” के तहत स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के लिए यूपी सरकार दृढ़ संकल्पित नजर आ रही है।

“बैंकिंग कॉरसपोडेंट सखी योजना” के तहत 58000 स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी। इस योजना से



ग्रामीण महिलाएं बैंकों से जुड़कर नकदी का लेनदेन घर-घर जाकर करवाएंगी। योजना के माध्यम से स्थानीय लोगों का निकासी और जमा डिजिटल रूप से होगा, खाता धारकों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

महिलाओं को “स्किल मैपिंग” के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसी सन्दर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, “प्रत्येक महिला में उद्यमिता के गुण और मूल्य होते हैं। यदि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों तो महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं”

“मास्क अप इंडिया” मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों (सेल्फ हेल्प ग्रुप्स) के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। हाल ही के आकड़ों को देखे तो प्रदेश में पर्सनल

प्रोएक्टिव इक्विपमेंट एवं मास्क सहित कुल लगभग 70 इकाइयाँ क्रियाशील हैं। वर्तमान में जब देश के भीतर मास्क की मांग बढ़ी है, तब स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं मास्क की आपूर्ति संपूर्ण देश में कर रही हैं।

उल्लेखनीय होगा कि महिलाओं को प्रदेश सरकार न केवल रोजगार उपलब्ध करा रही बल्कि उनके उत्पादों की मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग भी करा रही है। इस सन्दर्भ में जिक्र जरूरी होगा कि दिल्ली और बुलंदशहर में 3000 से भी अधिक स्थानीय ग्रामीण महिलाएं मास्क बनाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। बुलंदशहर स्थानीय प्रशासन के द्वारा डिजाइनर मास्क का निर्माण कर सम्पूर्ण देश में भेजा जा रहा है तथा छ: महीने में लगभग 50000 महिलाओं को जोड़कर उनको रोजगार उपलब्ध करने का प्रयास किया जा रहा है।

“मास्क अप इंडिया मिशन” के तहत कई गैर सरकारी संस्थाओं ने भी मुहिम छेड़ रखी है जिसके विषय में 25 जून, 2020 को प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्वीटर से यह भी बताया गया कि रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनती स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 50 हजार की पूंजी से 30 लाख कमाए जो कि बहुत ही सराहनीय है।

बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के “स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण” की दिशा में कार्य करते हुए यह भी निर्देश दिया गया कि मास्क का उपयोग न करने पर जिस व्यक्ति का चालान हो उसे ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित मास्क उपलब्ध कराया जाए।

महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कई घोषणाएं भी की गयी हैं। उदाहरणस्वरूप 86 लाख वृद्धावस्था, दिव्यांगजन तथा निराश्रित महिला लाभार्थियों को दो माह की पेंशन का भुगतान एक साथ किया गया है। 4 जून 2020 तक के आकड़ों के अनुसार निराश्रित महिला पेंशन धारकों के अकाउंट में 1500 की धनराशि तथा 130.31 मासिक पेंशन तथा “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना” पैकेज के तहत 260.62 करोड़ की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की गई।

इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा “उज्ज्वला योजना” के लगभग १.४७ करोड़

लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराये गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य भी है। “मुद्रा योजना” और “स्टैंडअप इंडिया” के तहत प्रदेश सरकार महिला लाभार्थियों को उद्योगों के लिए आर्थिक ऋण प्रदान कर रही है।

साथ ही साथ, निराश्रित महिला पेंशन हेतु आयु सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जा चुका है। किशोरियों में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से पहले से ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लाई गयी, सामूहिक विवाह के लिए सहायता धनराशि बढ़ाकर 51000 कर दिया गया, पोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी के लिए “पोषण पखवाड़ों” का आयोजन करने जैसे काम किए गए हैं।

वर्तमान में, 12 जून को प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई कि “बाल श्रमिक विद्या योजना” के तहत बालिकाओं को 1200 की धनराशि प्रतिमाह तथा साथ ही साथ कक्षा 8, 9, 10 उत्तीर्ण करने पर प्रतिवर्ष 6000 की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। बच्चों को बालश्रम से अलग कर शिक्षा से जोड़ने हेतु योजना लागू करने वाला यूपी देश का प्रथम राज्य बन गया है।

प्रदेश सरकार उनकी प्रतिभा के अनुरूप उन्नति के अवसर उपलब्ध करने के लिए संकल्पित है। देश में महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में

रखते हुए “मिशन अनिवार्य” की शुरुआत की गयी है, जिसके तहत महिलाओं को मुफ्त में सैनेटरी पैड का वितरण भी किया जा रहा। दिल्ली एन.सी.आर से लेकर देश के अन्य जगहों पर सैनेटरी पैड के वितरण का कार्य भी सराहनीय है।

इसके अलावा लिखना आवश्यक होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे लॉकडाउन के दौरान अपनी सेवाओं, सहायता और जागरूकता के लिए प्रतिबद्ध नजर आई है। झाँसी की महिला पुलिस मास्क बना रही, वहीं उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश बॉर्डर पर “पैडमैन” की तरह प्रवासी महिलाओं को निःशुल्क सैनेटरी पैड के वितरण के कार्य द्वारा भी झाँसी खासा चर्चा में रहा है।

सभी प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दिशा में प्रदेश सरकार तथा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नारडको के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के 11 लाख श्रमिकों/कामगारों को रोजगार प्राप्त होगा जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं।

इससे स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को गति मिलेगी साथ ही साथ व्यापक स्तर पर लोगो को रोजगार भी प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अब महिलाओं के कल्याण के साथ-साथ उनके नेतृत्व के विकास का भी है। योगी सरकार राज्य, जिला, ग्रामीण स्तर पर विद्यमान संस्थागत

तंत्रों को मजबूती प्रदान करते हुए महिलाओं को सशक्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन, जरूरी प्रशिक्षण तथा समर्थनीय कौशल को सुनिश्चित कर रही है।

नए भारत के निर्माण की तरफ अग्रसर होते हुए देश की आधी आबादी की विकास प्रक्रिया में भागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए इसी सन्दर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने विगत वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा था, “सशक्त महिलाओं का मतलब है कि महिलाओं को अपने व्यक्तिगत लाभों के साथ ही साथ ही समाज के लिए अपने स्वयं के निर्णय ले सकने में सक्षम हो”।

इसकी प्रासंगिकता को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यह कहना उचित होगा कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी नए भारत के निर्माण को आधार प्रदान करती है। आवश्यकता है सकारात्मक सोच की; सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले परिवेश की; नीतियों का क्रियान्वयन कर महिलाओं के समावेशन की; स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, समान कार्य के लिए समान वेतन की और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर विकास प्रक्रिया में उनको शामिल करने की, जिससे वे अपने कौशल, अपनी क्षमता को मूर्त रूप प्रदान कर सकें।

(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कृषि-औद्योगिक विकास का आधार बनेगी केन-बेतवा नदी परियोजना

प्रमोद भार्गव

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इसकी सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। नतीजतन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रीमण्डल की बैठक में इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए 44,605 करोड़ रुपये की राशि देने का प्रावधान कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो अभियान की जो परिकल्पना की थी, उसे नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया है।

मोदी की मौजूदगी में मध्य-प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ों परियोजना के तहत केन और बेतवा नदियों को जोड़ने वाले समझौता-पत्र पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह मंजूरी जल शक्ति अभियान 'कैच द रन' के तहत अमल में लाई जाएगी। साफ है, इस परियोजना से कृषि तो फले-फूलेगी ही, कृषि आधारित उद्योग भी पनपेंगे और लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।

बाढ़ और सूखे से परेशान देश में नदियों के संगम की परियोजना मूर्त रूप लेने जा रही है, यह देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है। 5500 अरब रुपये की इस परियोजना

को जोड़ने का अभियान सफल होता है तो भविष्य में 60 अन्य नदियों के मिलन का रास्ता खुल जाएगा। दरअसल बढ़ते वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन और बदलते वर्षा चक्र के चलते जरूरी हो गया है कि नदियों के बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों के जरिए भेजा जाए।

ऐसा संभव हो जाता है तो पेयजल की समस्या का निदान तो होगा ही, सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त जल मिलने लग जाएगा। वैसे भी भारत में विश्व की कुल आबादी के करीब 18 प्रतिशत लोग रहते हैं और उपयोगी जल की उपलब्धता महज 4 प्रतिशत है।

कृत्रिम रूप से जीवनदायी नर्मदा और मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदियों को जोड़ने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके हैं। चूंकि ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश में बहती थीं, इसलिए इन्हें जोड़ा जाना संभव हो गया था। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की तैयारी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें बहुत पहले से जुटी थीं।

इस परियोजना को वर्ष 2005 में मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर विवाद बना हुआ था। उप्र को रबी फसल के लिए 547 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) और खरीद फसल के लिए 1153

एमसीएम पानी देना तय हुआ था। मुख्य विवाद रबी फसल के लिए पानी देने को लेकर था।

अप्रैल 2018 में उग्र ने इस फसल के लिए 700 एमसीएम पानी की मांग रखी, जो बाद में 788 एमसीएम तक पहुंच गई। इस पर सहमति बनती इससे पहले उग्र ने जुलाई 2019 में पानी की मांग बढ़ाकर 930 एमसीएम कर दी। मप्र इतना पानी देने को तैयार नहीं हुआ, लिहाजा विवाद बना रहा। किंतु अब केंद्र और दोनों प्रदेशों की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की होने के चलते 35,111 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है। परियोजना में पांच-पांच फीसदी राशि राज्य सरकारें खर्च करेंगी और 90 प्रतिशत की बड़ी राशि केंद्र सरकार देगी।

केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किमी उत्तर की ओर बहने के बाद बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर गिरती है। वहीं बेतवा नदी मध्य-प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किमी बहने के बाद उत्तर-प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिलती है। केन-बेतवा नदी जोड़ो योजना की राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीएड की रिपोर्ट के अनुसार डोढ़न गांव के निकट 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बांध बनाया जाएगा।

इसके डूब क्षेत्र में छतरपुर जिले के बारह गांव आएंगे। इनमें पांच गांव आंशिक रूप से और सात गांव पूर्ण रूप से डूब में आएंगे। कुल 7000 लोग प्रभावित होंगे। इन्हें विस्थापित करने में इसलिए समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये ग्राम जिन क्षेत्रों में आबाद हैं, वे पहले से ही वन-संरक्षण

अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं। इस कारण रहवासियों को भूमि-स्वामी होने के बावजूद जमीन पर खेती से लेकर खरीद-बिक्री में पेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रामीण यह इलाका मुआवजा लेकर आसानी से छोड़ देंगे। ऐसा दावा प्राधिकरण की रिपोर्ट में कहा गया है।

इस परियोजना के बहुआयामी होने के दावे किए जा रहे हैं। बांध के नीचे दो जल-विद्युत संयंत्र लगाए जाएंगे। 220 किलोमीटर लंबी नहरों का जाल बिछाया जाएगा। ये नहरें छतरपुर, टीकमगढ़ और उत्तरप्रदेश के महोबा एवं झांसी जिले से गुजरेंगी। जिनसे 60,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। विस्थापन और पुनर्वास के लिए 213.11 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी, जिसका इंतजाम मंजूरी के साथ केंद्र सरकार ने कर दिया है।

डीपीआर के मुताबिक उत्तर-प्रदेश को केन नदी का अतिरिक्त पानी देने के बाद मध्य-प्रदेश करीब इतना ही पानी बेतवा की ऊपरी धारा से निकाल लेगा। परियोजना के दूसरे चरण में मध्य-प्रदेश चार बांध बनाकर रायसेन और विदिशा जिलों में नहरें बिछाकर सिंचाई के इंतजाम करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इन प्रबंधनों से केन में अकसर आने वाली बाढ़ से बर्बाद होने वाला पानी बेतवा में पहुंचकर हजारों एकड़ खेतों में फसलों को लहलहाएगा।

मध्य-प्रदेश का यही वह मालवा क्षेत्र है, जहां की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण सोना उगलती है। इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि खेत साल में 2 से लेकर 3 फसलें तक देने लग जाएंगे ? लेकिन मालवा की जो बहुफसली

बांध और नहरों में नष्ट होगी, उससे होने वाले नुकसान का आकलन प्राधिकरण के पास नहीं है ?

देश की विभिन्न नदियों को जोड़ने का सपना स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद देखा गया था। इसे डॉ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, डॉ राममनोहर लोहिया, अटलबिहारी वाजपेयी और डॉ एपीजे अब्दुल कलाम जैसी हस्तियों का समर्थन मिलता रहा है।

हालांकि परतंत्र भारत में नदियों को जोड़ने की पहली पहल ऑर्थर कॉटन ने बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में की थी। लेकिन इस माध्यम से फिरंगी हुकूमत का मकसद देश में गुलामी के शिकंजे को और मजबूत करने के साथ, बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा का दोहन भी था। क्योंकि उस समय भारत में सड़कों और रेल-मार्गों की संरचना पहले चरण में थी, इसलिए अंग्रेज नदियों को जोड़कर जल-मार्ग विकसित करना चाहते थे।

हालांकि आजादी के बाद 1971-72 में तत्कालीन केंद्रीय जल एवं ऊर्जा मंत्री तथा अभियंता डॉ कनूरी लक्ष्मण राव ने गंगा-कावेरी को जोड़ने का प्रस्ताव भी बनाया था। राव खुद जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकारों में जल संसाधन मंत्री भी रहे थे। लेकिन जिन सरकारों में राव मंत्री रहे, उन सरकारों ने इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को कभी गंभीरता से नहीं लिया।

करीब 13500 किमी लंबी ये नदियां भारत के संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में अठखेलियां करती हुई मनुष्य और जीव-जगत के लिए प्रकृति का अनूठा और बहुमूल्य वरदान

बनी हुई हैं। 2528 लाख हेक्टेयर भू-खण्डों और वन प्रांतों में प्रवाहित इन नदियों में प्रति व्यक्ति 690 घनमीटर जल है।

कृषि योग्य कुल 1411 लाख हेक्टेयर भूमि में से 546 लाख हेक्टेयर भूमि इन्हीं नदियों की बदौलत प्रति वर्ष सिंचित की जाकर फसलों को लहलहाती हैं। यदि नदियां जोड़ अभियान के तहत केन-बेतवा नदियां जुड़ जाती हैं तो इनकी अविरल बहने वाली धारा टूट सकती है। गोया, नदियों को जोड़ने से पहले टिहरी बांध के गंगा पर पड़ रहे प्रभाव और उत्तराखण्ड में बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं का भी आकलन करना जरूरी है ?

हालांकि केन और बेतवा का प्रवाह ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में है, इसीलिए यहां उत्तराखंड जैसे हालात कभी नहीं बनेंगे। बावजूद बुंदेलखण्ड में जो 4000 तालाब हैं, उन्हें और उनमें मिलने वाली जलधाराओं को संवारा जाए। इस काम में धन भी कम खर्च होगा और एक-एक कर तालाबों को संवारने में समय भी कम लगेगा। इनके संवरते ही पेयजल व सिंचाई की सुविधाएं भी तत्काल बुंदेलखण्डवासियों को मिलने लग जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर तालाब नहरों से पहले से ही जुड़े हुए हैं।

वैसे भी किसी काल्पनिक डर के चलते किसी महत्वाकांक्षी परियोजना पर ज्यादा शंका-कुशंकाएं न करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

योगी राज में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे क्रांतिकारी सुधार

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को विरासत में बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं मिली थी। शिक्षा की गुणवत्ता, अनियमित सत्र, नकल, फर्जी डिग्री, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार आदि से संबंधित अनेक समस्याएं थीं। लेकिन पिछले दो वर्षों में ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है।

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और माध्यमिक व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा इस उपलब्धि पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सरकार को सत्र नियमित करने, नकल विहीन परीक्षा कराने, पारदर्शिता लाने आदि कार्यों में शत-प्रतिशत और अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सर्वोत्तम बनाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

उनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में विसंगति समाज के लिए हानिप्रद होती है। वर्तमान सरकार के पहले नकल व्यवसाय चल रहा था। इस सरकार ने नकल रोकी। इसके बाद पांच लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ी। जांच में पता चला कि बड़ी संख्या में फर्जी विद्यार्थी थे, चार पांच जगहों से हजारों लोग

फार्म भरते थे। छात्रों के उत्पीड़न के बिना नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित की गई। पढ़ाई के समय और गुणवत्ता में वृद्धि की गई। अवकाश कम किये गए। एक पाठ्यक्रम लागू किया।

देश में सबसे सस्ती पुस्तकें उत्तर प्रदेश में ही मिल रही हैं। माध्यमिक शिक्षा में कलेंडर लागू किया। उसी के अनुरूप पढ़ाई, परीक्षा सुनिश्चित हुई। शिक्षकों की कमी भी दूर की जा रही है। अधिकारियों के स्थानांतरण की पारदर्शी प्रणाली लागू की गई। यह व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है।

प्रत्येक जोन में मॉडल स्कूल स्थापित किये गए हैं। इसमें समाज का सहयोग लिया जा रहा है। ढाई महीने चलने वाली परीक्षा मात्र सोलह दिन में होने लगी है। यह क्रान्तिकारी सुधार है। रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। महापुरुषों के नाम पर शोध पीठ बनाई जा रही है।

देश में सबसे सस्ती पुस्तकें उत्तर प्रदेश में ही मिल रही हैं। माध्यमिक शिक्षा में कलेंडर लागू किया। उसी के अनुरूप पढ़ाई, परीक्षा सुनिश्चित हुई। शिक्षकों की कमी भी दूर की जा रही है। अधिकारियों के स्थानांतरण की पारदर्शी प्रणाली लागू की गई। यह व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है।

प्रत्येक जोन में मॉडल स्कूल स्थापित किये गए हैं। इसमें समाज का सहयोग लिया जा रहा है। ढाई महीने चलने वाली परीक्षा मात्र सोलह दिन में होने लगी है। यह क्रान्तिकारी सुधार है। रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। महापुरुषों के नाम पर शोध पीठ बनाई जा रही है।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा का फंड बढ़ाया है। लेकिन फंड के साथ ईमानदारी से कार्य करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। अन्यथा फंड भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। पिछली सरकारों में ऐसा ही होता था। मगर, वर्तमान सरकार में फंड का पारदर्शी उपयोग होता दिख रहा है। इससे बड़ा सुधार हुआ है। सरकार के सुधारों के परिणामस्वरूप दो वर्ष में बीस प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या बोर्ड में बढ़ गई।

छोटे बच्चों पर बस्ते का बोझ अधिक नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के अलावा उनमें किसी खास

हुनर का विकास करने पर जोर देना जरूरी है। संगीत, कला, पर्यावरण, खेल आदि किसी क्षेत्र में इन्हें रुचि के अनुसार भेजना चाहिए। ये सभी कार्य पढ़ाई के साथ चल सकते हैं। यूपी सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। दिनेश शर्मा कहते हैं कि बच्चों को मेधावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यही देश के कर्णधार बनेंगे। योग्यता के आधार पर ही नम्बरों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, स्वस्थ प्रतियोगिता को सरकार बढ़ावा दे रही है।

पिछली सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। कुछ वर्ष पहले तक सत्र नियमित नहीं थे, नियमित दीक्षांत समारोह के प्रति पर्याप्त सजगता का भाव नहीं था। गुणवत्ता की भी समस्याएं थीं। उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। कुलपतियों के सम्मेलन के माध्यम से विचार विमर्श का दौर चला। सत्र नियमित हुए। सत्र नियमित होते हैं, तो विद्यार्थियों का अमूल्य समय बर्बाद नहीं होता। स्पष्ट है कि राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यापक सुधार देखने को मिले हैं। यही कारण है कि विदेशी अखबारों ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था के विषय में लिखा कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार हो रहा है।

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

योगी आदित्यनाथ : कोविड काल में सुशासन का आदर्श स्थापित करने वाले मुख्यमंत्री

प्रणय कुमार

स

च ही कहा गया है कि एक संन्यासी ही अच्छा शासक हो सकता है। प्राचीन भारत में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते ही हैं, स्वातंत्र्योत्तर भारत में भी इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। अधिक दूर क्यों जाएँ, उत्तर प्रदेश को ही देखें।

उत्तर प्रदेश जैसे विस्तृत भूभाग एवं विशाल जनसंख्या वाले प्रदेश की जटिलताएँ और समस्याएँ कौन नहीं जानता! और 2017 से पूर्व के विगत एक दशक से वहाँ पनपे अपराध, भयावह तुष्टिकरण, जर्जर तंत्र, राजनीति के अपराधीकरण आदि ने उसकी जो दुर्दशा कर रखी थी, वह किसी से छुपी नहीं।

बाहुबलियों और शोहदों के हौसले बुलंद थे और सज्जन शक्तियाँ पस्त-विवश-भयभीत थीं। उद्योग-धंधे, कल-कारखानों के विस्तार के लिए प्रदेश में अनुकूल माहौल नहीं था। जो जमे-जमाए थे वे भी राज्य छोड़कर अन्यत्र जाने का मन बनाने लगे थे।

ऐसे में, योगी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व संभाला। उनके अल्पावधि के शासन-काल में ही सुराज एवं सुशासन की आशा जगी। उनके अहर्निश परिश्रम-पुरुषार्थ एवं लोकमंगल की भावना को देखकर यह प्रतीत होता है कि एक संन्यासी यदि राज्य का मुखिया (शासक) हो तो जनता सचमुच रामराज्य की संकल्पना के साकार होने की उम्मीद सँजोने लगती है।

कहा जाता है कि जीवन के आदर्श ही व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। महान भारतवर्ष राजा राम को अपना आदर्श मानता आया है। गाँधी भी रामराज्य की बात करते थे। लोक-मन ने तपस्वी राम और राजा राम दोनों को सदा से अपने हृदय में बहुत ऊँचे आसन पर रखा।

राजा राम का परिश्रमी, पुरुषार्थी, प्रजा-वत्सल स्वरूप और तपस्वी राम का त्यागी, वैरागी, निर्लोभी, जितेंद्रिय स्वरूप- निश्चित ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भीतर-ही-भीतर प्रेरित-प्रोत्साहित-आंदोलित करता होगा। वे

राजा राम और तपस्वी राम-दोनों के पदचिह्नों के अनुसरण को अपना परम सौभाग्य मानते होंगे।

और इसीलिए प्रदेश की सत्ता सँभालते ही उन्होंने शासन-प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करते हुए सबसे पहले अपराधियों, बाहुबलियों एवं शोहदों पर नकेल कसी। उत्तर प्रदेश को अपराध-मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में जो-जो कठोर एवं आवश्यक कदम उठाए जाने थे, उठाया।

प्रदेश में दशकों से अपराध और राजनीति की गठजोड़ से समानांतर सत्ता चलाने वालों ने योगी सरकार की साख एवं लोकप्रियता पर ग्रहण लगाने के अनेकानेक कुचक्र रचे, उनकी छवि को धूमिल एवं कलंकित करने के खूब षड्यंत्र किए। पर उनके लाख प्रयासों के बावजूद योगी संघर्षों और आरोपों की आग में तपकर कुंदन ही बने। उनकी चमक फीकी न पड़ने पाई।

उनके विरोधी भी दबे स्वर में स्वीकार करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है और अपराधियों में इस प्रकार का भय पैठा है कि वे या तो राज्य छोड़कर अन्यत्र चले जा रहे हैं या जेल में ही रहना पसंद करने लगे हैं। योगी जी ने अतिरिक्त प्रयासों एवं नीतिगत पहल से प्रदेश में विकास एवं निवेश को गति प्रदान की है।

उत्तर प्रदेश में विकास की गाड़ी पटरी पर आने ही लगी थी कि कोविड-19 के प्रकोप और प्रसार ने संपूर्ण विश्व में त्राहिमाम मचा दिया। जिस कोविड

से लड़ने में पूरी दुनिया मुख्यतया विकसित देशों की सरकारें भी हाँफती नज़र आई, उससे योगी और उनकी सरकार ने अद्भुत लड़ाई लड़ी। जो योद्धा होते हैं वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर चुनौतियों को भी अवसर में परिवर्तित कर देते हैं।

योद्धा सन्यासी योगी आदित्यनाथ ने भी कोविड और उसकी चुनौतियों को अवसर में परिणत कर दिया और ऐसे आशातीत-आश्चर्यकारी परिणाम दिए कि पूरी दुनिया दाँतों तले ऊँगली दबाकर बस देखती रह गई! उत्तर प्रदेश जैसे विशाल एवं घनी-बड़ी आबादी वाले प्रदेश में उन्होंने जिस सक्रियता एवं मुस्तैदी से कोविड की रोक-थाम के लिए काम किया वह अद्वितीय, असाधारण, अभूतपूर्व है। कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार हर पल, हर कदम पर सन्नद्ध, सक्रिय और सचेष्ट दिखाई दी।

तब्लीगियों पर कड़ी निगरानी एवं सख्त कार्रवाई करने से लेकर पीपीई किट्स उपलब्ध कराने, व्यापक पैमाने पर परीक्षण कराने से लेकर संक्रमितों की विधिवत देख-भाल के लिए स्थाई-अस्थायी कोविड-केंद्र खुलवाने, कोविड-पीड़ितों के दस्तावेजीकरण से लेकर उनके आइसोलेशन की व्यवस्था, प्रभावित मरीजों के लिए वेंटीलेटर्स-बेड्स से लेकर चिकित्सकीय उपकरण-उपचार आदि उपलब्ध कराने तक, शायद ही ऐसा कोई मोर्चा हो जिस पर प्रदेश की सरकार नीति, निर्णय

या नीयत के स्तर पर किसी प्रकार के द्वंद्व या दुविधा की शिकार दिखी हो।

केवल प्रदेश ही क्यों, जब कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोविड से उत्पन्न विकट परिस्थितियों को अनियंत्रित होता देख अपने-अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया तो मुख्यमंत्री योगी ने बड़े मन एवं उदार हृदय से उनकी भी सहायता की।

सभी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा-मानकों का पालन करते हुए दिल्ली से बिहार के लिए कूच कर रहे प्रवासी मजदूरों को राज्य की सीमा तक पहुँचाने का उन्होंने जैसा प्रबंध किया, वह उनके योग्य एवं कुशल प्रशासक होने के साथ-साथ मानवीय एवं संवेदनशील होने का भी प्रत्यक्ष प्रमाण था।

लॉकडाउन के दौरान कोटा में फँसे उत्तर प्रदेश एवं बिहार के विद्यार्थियों को सकुशल उनके घर पहुँचाने का उनका प्रयास भी जन-सरोकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एवं संवेदनशीलता को दर्शाता है। वे केवल कोविड के अप्रसार तक ही नहीं रुके, बल्कि इसी अवधि में वे शासन-प्रशासन के तमाम मोर्चों पर देश को राह दिखाते भी नज़र आए।

नोएडा में देश की सबसे बड़ी फ़िल्म-सिटी निर्माण के लिए उनके द्वारा किया जा रहे अनथक परिश्रम और सार्थक पहल उनकी दूरदर्शिता का ही परिचायक है। और जिस दौर एवं परिवेश में उन्होंने ऐसी घोषणा एवं पहल की वह भी बहुत-से

निहितार्थों और संदेशों को अपने भीतर समाहित किए हुए है।

विश्व के सबसे बड़े हवाईअड्डे एवं विकास की अन्य परियोजनाओं पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी तेजी से काम प्रारंभ किया है। एक ओर वे मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत तथा लोकल फ़ॉर वोकल की अपील के बाद घरेलू निवेशकों को आमंत्रित करते नज़र आए तो दूसरी ओर चीन से खिन्न एवं क्षुब्ध विदेशी कंपनियों को लुभाने में भी उन्होंने कोई संकोच नहीं दिखाया।

तमाम विकसित देशों की मिली-जुली संख्या से भी अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते योद्धा संन्यासी योगी आदित्यनाथ ने जिस कुशलता, तत्परता एवं निष्ठा से कोविड का मुकाबला किया है वह उन्हें कोविड-काल के महानायक-सी हैसियत प्रदान करते हैं।

नीतियों, निर्णयों, कार्यों और उनके बेहतर परिणामों के आधार पर योगी आदित्यनाथ को वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। उन्होंने इस संकटकालीन समय के सशक्त सारथी या जागरूक प्रहरी की भूमिका का कुशल निर्वहन किया। शासक जब संन्यासी हो या संन्यासी ही शासक हो तो प्रजा निश्चित ही सुखी, निश्चित और आश्वस्त महसूस करती है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

कोरोना संकट में अपने सधे हुए क़दमों से स्थिति को नियंत्रित रखने में कामयाब योगी सरकार

नवोदित सक्तावत

को रोना वायरस की महामारी की जकड़ में देश व दुनिया का हर आम व खास है। शहरी क्षेत्रों में संक्रमण के हॉटस्पॉट को नियंत्रित करना राज्यों के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए यह चुनौती बढ़ जाती है क्योंकि यहां जिलों की संख्या और आबादी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। इस समय लॉकडाउन का तीसरा दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रशासनिक क्षमता एवं प्रबंधन कौशल का परिचय देते हुए राज्य में हालात को काबू में रखा हुआ है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था।

जब देश में लॉकडाउन घोषित हुआ था तब चार दिन पहले ही बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर ने बड़ी लापरवाही दिखाई और स्वयं संक्रमित होते हुए भी सार्वजनिक रूप से घूमकर, लोगों से मिलकर हजारों की जान को खतरे में डाल दिया। गनीमत है कि उस समय देश में संक्रमण प्राथमिक स्टेज पर था, अन्यथा यदि यह मास ट्रांसमिशन की श्रेणी में होता तो बेकाबू हो सकता था। यूपी जैसे

देश की सर्वाधिक और घनी आबादी वाले राज्य में इसे लेकर लोगों के मन में भय था कि यदि समय पर हालात कंट्रोल नहीं हुए तो संक्रमण भयानक रूप ले सकता है और स्थिति संभाले नहीं संभलेगी।

लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभालते हुए हर स्थिति पर नजर बनाए रखी। उन्होंने बैठकों का दौर जारी रखा, अधिकारियों के साथ मिलकर ना केवल नीतियां बनाईं बल्कि धरातल पर उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया। लॉक डाउन में गरीबों को राहत देने के लिए उनके खाते में 1000 रुपये भेजने का काम सफलतापूर्वक किया गया। आंकड़ों के मुताबिक तक्ररीबन 29 लाख मजदूरों के खाते में यह सहायता राशि भेजी गयी है।

कोरोना संक्रमण से लड़ाई के दौरान ही योगी के पिता के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ लेकिन उन्होंने राजधर्म निभाते हुए निजी शोक की घड़ी में भी अपना धैर्य नहीं खोया। प्रदेश के 23 करोड़ देशवासियों की सेवा में उन्होंने पिता की अन्त्योष्टि में न जाने का निर्णय लेकर समाज के

सामने एक आदर्श स्थापित किया। इन बातों से पता चलता है कि वे अपने राज्य की सलामती को लेकर कितने कृत संकल्पित भाव से कार्य कर रहे हैं।

योगी ने केवल राज्य के भीतरी हालात ही नहीं संभाले बल्कि यूपी के जो श्रमिक अन्य राज्यों से यहां आने के लिए पैदल ही चल पड़े थे, उनकी भी व्यवस्था की। लॉक डाउन के दो दिन बाद ही दिल्ली से मजदूरों का जत्था पैदल ही निकल पड़ा था, जिसे योगी सरकार ने ले जाकर क्वारंटाइन में रखा और उनकी समस्त व्यवस्थाएं की। राजस्थान के कोटा में फंसे प्रदेश के दस हजार छात्रों को उनके गृहक्षेत्र तक सकुशल पहुंचाने का भी काम सरकार ने किया है।

कोचिंग के छात्र-छात्राओं को उनके घर तक पहुंचाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूर तथा गरीब लोग हैं। इनके लिए वे जनकल्याणकारी नीतियों का भी ध्यान रख रहे हैं। सभी राज्यों से प्रदेश के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को वापस अपने क्षेत्र लाने के लिए प्रभावी व्यवस्था की गई। इस क्रम में एक बड़ा अभियान हेलपलाइन नंबर जारी करने के रूप में सामने आया। सरकार ने सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रवासी श्रमिकों के नाम, पते, टेलीफोन नम्बर और स्वास्थ्य परीक्षण आदि की डिटेल मांगी है।

राज्य के भीतर भी हर वर्ग, हर व्यक्ति के लिए

योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभालते हुए हर स्थिति पर नजर बनाए रखी। उन्होंने बैठकों का दौर जारी रखा, अधिकारियों के साथ मिलकर ना केवल नीतियां बनाईं बल्कि धरातल पर उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया। लॉक डाउन में गरीबों को राहत देने के लिए उनके खाते में 1000 रुपये भेजने का काम सफलतापूर्वक किया गया। आंकड़ों के मुताबिक तक्ररीबन 29 लाख मजदूरों के खाते में यह सहायता राशि भेजी गयी है।

बुनियादी इंतजाम जुटाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। इस क्रम में सबसे पहले होम क्वारंटाइन के लिए लोगों की निगरानी करने के लिए निगरानी समितियों का गठन किया जा रहा है। इन समितियों में युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, एनसीसी आदि का सहयोग लिया जाएगा। समिति सदस्य क्वारंटाइन सेंटर अथवा शेल्टर होम से प्रवासी मजदूरों का हेल्थ चेकअप करके उन्हें घर भेजेंगे एवं उन्हें राशन की एक किट भी प्रदान करेंगे।

एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर एवं कम्युनिटी किचन तैयार किए जा रहे हैं ताकि बाहर से आने वाले अप्रवासी श्रमिकों को यहां पर रोका

व ठहराया जा सके। राजधानी दिल्ली से सटे उग्र के औद्योगिक क्षेत्र नोएडा एवं गाज़ियाबाद से छात्रों व कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।

जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में भी अन्य मुख्यमंत्रियों से कुछ हटकर काम किया है। वे स्वयं अस्पतालों में जाकर वहां की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। राज्य में पीपीई

किट, एन-95 मास्क समेत अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्ध सुनिश्चित की गई है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इस काम में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सहयोग कर रहा है।

इस समय सबसे अधिक संवेदनशील बिंदु बाहर से आने वाले लोगों का है, क्योंकि उन्हें स्वयं नहीं पता कि वे संक्रमित हैं या नहीं। एक संक्रमित व्यक्ति कई को चपेट में ले सकता है। इसलिए इस समय हर प्रवेश स्थान पर इंफ्रारेड थर्मामीटर जरूरी है ताकि प्रवासियों के शरीर का तापमान जांचा जा सके। उनके कार्यों एवं निर्णयों में उनका संकल्प परिलक्षित हो रहा है कि वे किस प्रकार एक-एक कदम सोच-समझकर से रख रहे हैं और सधे हुए कदमों से अपने प्रदेश को महामारी से बचाने में अबतक सफलतापूर्वक जुटे हुए हैं।

योगी की सजग और सूझबूझ भरी कार्यशैली का ही परिणाम है कि यूपी जैसे देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में अबतक कम आबादी वाले देश के राज्यों की तुलना में मामले कम हैं और स्थिति नियंत्रित है। निश्चित ही योगी ने जिस तरह इस स्थिति को संभाला है, वो देश के सभी राज्यों और मुख्यमंत्रियों के लिए प्रेरणादायक है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोचिंग के छात्र-छात्राओं को उनके घर तक पहुंचाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूर तथा गरीब लोग हैं। इनके लिए वेजनकल्याणकारी नीतियों का भी ध्यान रख रहे हैं। सभी राज्यों से प्रदेश के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को वापस अपने क्षेत्र लाने के लिए प्रभावी व्यवस्था की गई। इस क्रम में एक बड़ा अभियान हेल्पलाइन नंबर जारी करने के रूप में सामने आया। सरकार ने सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रवासी श्रमिकों के नाम, पते, टेलीफोन नम्बर और स्वास्थ्य परीक्षण आदि की डिटेल मांगी है।

योगी सरकार की उपलब्धियों से बौखलाहट में विपक्ष

नवोदित सक्तावत

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की पुलिस, आतंकरोधी दस्ते ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। राजधानी लखनऊ से आतंकी संगठन अलकायदा के दो आतंकी धरे गए। इसके अलावा काकोरी से भी एटीएस ने दो आतंकियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रदेश में रची जा रही बहुत बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हो गया। यूपी पुलिस की सूझबूझ और सक्रियता से आतंकी हमले के मंसूबे नाकाम हो गए।

पकड़े गए आतंकियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे प्रदेश के 8 शहरों में आगामी स्वतन्त्रता दिवस के आसपास सीरीयल ब्लास्ट करने वाले थे। धरपकड़ में पुलिस को इनसे प्रेशर कुकर बम, टाइम बम और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। यहां तक सब कुछ साफ सुथरा और स्पष्ट है कि हजारों लोगों की जान बचा ली गई।

निश्चित ही यह संतोष और प्रसन्नता का विषय है। लेकिन आश्चर्यजनक है कि पुलिस की इस प्रभावी कार्रवाई से सपा नेता अखिलेश यादव

असंतुष्ट हैं। उनके साथ ही पूर्व सीएम मायावती भी बहुत प्रसन्न नहीं हैं। सवाल है कि यदि आतंकी विस्फोट की साजिश रच रहे थे और वे पकड़े जाते हैं तो यह संतोष का विषय होना चाहिये या शिकायत का ? इससे तो यह प्रतीत होता है जैसे अखिलेश और मायावती इन आतंकियों की पैरवी कर रहे हों।

अखिलेश ने एक बयान में कहा कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, वहीं मायावती कहती हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले ऐसी कार्रवाई अविश्वसनीय है। यदि हम अखिलेश की बातों पर गौर करें तो पाएंगे कि उन्हें आतंकी साजिश नाकाम होने की जरा भी खुशी नहीं है। साथ ही, यदि वे कहते हैं कि उन्हें यूपी पुलिस और भाजपा पर भरोसा नहीं है तो सवाल उठता है कि फिर उन्हें भरोसा किसपर है ? क्या अखिलेश यह चाहते हैं कि आतंकी साजिशें सफल हो जाएं।

जरा याद कीजिये, यूपीए की सरकार में एक दशक पहले का दौर जब देश के कई शहरों में एक के बाद एक लगातार बम विस्फोट हुए थे और हजारों लोगों की मौत हुई थी। 2007 में उत्तर

पकड़े गए आतंकियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे प्रदेश के 8 शहरों में आगामी स्वतन्त्रता दिवस के आसपास सीरीयल ब्लास्ट करने वाले थे। धरपकड़ में पुलिस को इनसे प्रेशर कुकर बम, टाइम बम और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। यहां तक सब कुछ साफ सुथरा और स्पष्ट है कि हजारों लोगों की जान बचा ली गई।

प्रदेश के कई शहरों में सीरीयल ब्लास्ट हुए थे। अब जबकि ऐसे साजिशों को अंजाम दिए जाने से पहले ही ध्वस्त किया जा रहा है तो इसमें अखिलेश यादव को इतनी समस्या क्यों हो रही है। उनकी यह समस्या बहुत कुछ बयां करती है।

इससे पहले भी अखिलेश कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताकर अपनी हंसी उड़वा चुके हैं। आज वे वैक्सीन और एटीएस पर सवाल उठा रहे हैं। पांच साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों में वे भी शामिल थे। इसमें नया कुछ नहीं है।

उनके इस बेसिर पैर के बयान के बाद भाजपा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनकी जमकर खबर ली और कहा कि एक तरफ जहां पुलिस अपने जीवन

को ताक पर रखकर आतंकियों को पकड़ रही है, वहीं अखिलेश यादव को इस पुलिस पर भरोसा नहीं हो रहा है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में आतंकवादियों के केस वापस लेने का प्रयास किया था।

यदि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है तो फिर वे खुद बताएं कि उन्हें किस पर भरोसा है। क्या उन्हें उन पर भरोसा है जो सपा के शासनकाल में दंगाइयों को हेलीकाप्टर में बैठाकर मुख्यमंत्री कार्यालय ले जाकर स्वागत कर रहे थे। कांग्रेस के शासन में तो आतंकियों को जेल में भी बिरयानी खिलाई गई थी। बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आंसू तक छलक आए थे।

देश की सुरक्षा के लिए तो पुलिस और सेना बारहों महीने काम करती है, ऐसे में मायावती के इस बेतुके बयान का भी भी कोई औचित्य नहीं है कि यह चुनाव से पहले क्यों किया गया। यदि चुनाव के पहले एटीएस ने आतंकी मोड्यूल पकड़ा है तो इससे तो संदेश जाता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता एवं सतर्क है। इसमें भी खुश होने की बजाय मायावती का प्रतिकूल बयान उनकी भी विचारधारा को स्पष्ट करता है।

असल में यह समस्या अकेले अखिलेश या मायावती की नहीं, बल्कि समूचे विपक्ष की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2017 से लेकर अभी



तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सफल साबित हुए हैं। उन्होंने प्रदेश में ना केवल गुंडागर्दी को नियंत्रित किया, बल्कि अपराध भी घटे हैं। कोरोना महामारी में भी उत्तर प्रदेश को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया एवं कुशल आपदा प्रबंधन के चलते अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल कायम की। इससे विपक्ष बौखलाया हुआ है।

अब जहां तक राजनीतिक बढ़त की बात है, तो इस मामले में भी योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश-मायावती से लेकर कांग्रेस तक सब फीके ही नजर आ रहे। राज्य में पंचायत स्तर से

लेकर जिला स्तर तक सपा सिमट गई है।

ऐसे में अपनी बची खुची जमीन बचाने के लिए अखिलेश बयानबाजी तो कर रहे हैं लेकिन बौखलाहट में वे प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा पर कुछ ऐसा बोल गए हैं जिससे उनकी ही सर्वत्र किरकिरी हो रही है। वे पहले भी बड़बोले थे और अब भी उनमें कोई सुधार नहीं आया है। उनका यह बड़बोलापन प्रदेश की जनता बखूबी समझ रही है। यूपी में आतंकवाद सहित इन्हें पोषित करने वाली ताकतों को चुनाव में जनता जरूर जवाब देगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

यूपी : योगी राज में एक-एक कर ध्वस्त हो रहा अपराधियों का आर्थिक साम्राज्य

प्रणति तिवारी मुखर्जी

दे श के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार सौ प्रतिशत प्रतिबद्ध दिख रही है। यह वाकई काबिले तारीफ है। यहां कई ऐसे कुख्यात अपराधियों का साम्राज्य रहा है जो राजनीतिक दलों के आंचल तले अपराध को अंजाम देते रहे हैं और दहशत व पाप की कमाई से करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन कर बैठे हैं।

अपराध से कमाई गई संपत्तियों को पीढ़ियों से कई राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिलता रहा है और ये पार्टियाँ हर चुनाव व राजनीतिक मोर्चों पर बदले में इन अपराधियों की गुंडागर्दी व दहशत का फायदा लेती रही हैं। ऐसे में राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए आज जिस प्रकार योगी सरकार 360 डिग्री पर काम करती दिख रही है, वह वाकई जनता के लिए बड़ी सुकून की बात है।

अपराध मुक्त राज्य के वादे के तहत योगी सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ

एक और मोर्चा खोलते हुए अब उनकी पाप की कमाई का हिसाब-किताब शुरू कर दिया है।

सरकार उन तमाम संपत्तियों का हिसाब किताब कर रही है जो दहशत और बाहुबल से कब्जाई गई निजी और सरकारी संपत्ति हैं। इन संपत्तियों को कब्जामुक्त बनाने के लिए आदेश जारी किया जा चुका है। इसके लिए योगी सरकार ने लिस्ट भी बनाई है और उन तमाम संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है जो अपराध के पैसों से बनी हों अथवा कानून के बाहर जा कर कभी कब्जाई गयी हों।

इस तरह यह साफ है कि सरकार यह बताना चाहती है कि अपराधी के साथ उसके आर्थिक साम्राज्य को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसी क्रम में राज्य के उन बाहुबली विधायकों की संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है जो कभी अपराध जगत में सक्रिय रहकर संपत्ति बनाए और आज राजनीतिक पार्टियों में नेता बन चुके हैं।

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लखनऊ स्थित अवैध भवन पर बुलडोजर चलाया

गया। यह पहला मौका था जब मुख्तार अंसारी के परिवार की अवैध संपत्तियों पर किसी सरकार ने शिकंजा कसा है। अंसारी की लखनऊ के प्राइम लोकेशन पर मौजूद दूसरी संपत्तियों को भी खंगाला जा रहा है।

गुरुवार को कार्रवाई के तहत जिला प्रशासन, एलडीए और पुलिस की टीम ने विधायक मुख्तार अंसारी के लखनऊ में डालीबाग स्थित अवैध भवन को बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। इसके अलावा सरकार ने मुख्तार अंसारी गिरोह के 12 अपराधियों को छह माह के लिए जिलाबंदर भी किया है।

दरअसल मऊ सदर सीट से विधायक मुख्तार ने जिस जमीन पर भवन निर्माण किया था वह निष्क्रांत संपत्ति के अंतर्गत आती है। जानकारी दे दें कि आजादी के बाद जो लोग देश छोड़कर चले गए उनकी संपत्तियां सरकारी प्रोपर्टी मानी गईं।

इन संपत्तियों को दो श्रेणियों में रखा गया। एक को शत्रु संपत्ति और दूसरी निष्क्रांत संपत्ति। इनमें मार्च 1954 से पहले गए लोगों की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति के अंतर्गत रखा गया और इसके बाद जाने वालों की संपत्तियों को निष्क्रांत संपत्ति माना गया।

इस तरह यह सरकारी संपत्ति के तहत आई जिस पर मुख्तार ने अपना भवन बनाया था। लखनऊ के अलावा वाराणसी में भी माफिया

मुख्तार अंसारी के गुर्गे प्रकाश मिश्र उर्फ झुन्ना पंडित की 58 लाख से अधिक की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई थी।

इसके अलावा अंसारी के करीबी मछली तस्कर रवींद्र निषाद उर्फ पप्पू की करीब पांच करोड़ रुपये की संपत्ति अबतक सील की जा चुकी है। जबकि गैंगस्टर एक्ट के तहत जौनपुर में पूर्व सांसद उमाकांत यादव के पुत्र दिनेशकांत यादव समेत 11 आरोपितों की करीब साढ़े चार करोड़ की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई जारी है।

उधर, भू-माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज में करीब 25 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को पहले ही जब्त व कुर्क किया जा चुका है। बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने खुल्दाबाद स्थित चकिया मोहल्ला स्थित करीब ढाई करोड़ रुपये के दो मकान व थाना धूमनगंज के कालिन्दीपुरम में इसी कीमत के दो मकान जब्त व कुर्क किए हैं।

इसी सिलसिले में सिविल लाइन में एमजी मार्ग स्थित करीब 20 करोड़ रुपये का मकान भी पुलिस जब्त कर चुकी है और अभी कई संपत्तियों पर कार्रवाई की जानी है। निश्चित रूप से सरकार के इस कदम से ना सिर्फ अपराधियों का हौसला कम होगा बल्कि समाज भी भयमुक्त हो कर विकास की सीढ़ी चढ़ेगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

क़ानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार के मॉडल से अन्य राज्यों को लेनी चाहिए प्रेरणा

प्रणति तिवारी मुखर्जी

योगी सरकार के आने के बाद से ही यूपी अपनी क़ानून-व्यवस्था के लिए चर्चा में बना रहा है। राज्य की क़ानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार किस तरह सजग है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां के नामी गैंगस्टर और गुंडे जान बचाने के लिए दर-ब-दर छिपते फिर रहे हैं।

दरअसल क्राइम के मामले में कई दशकों से बदनाम रहे यूपी की क़ानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने जैसे को तैसा वाली रणनीति अपना ली है। सूबे में बढ़ते संगठित अपराधों को रोकने के लिए योगी सरकार हर संभव प्रयास में है और आम जनता योगी सरकार के प्रयासों को सिर आंखों पर ले रही है।

योगी सरकार के कार्यों की बात करने से पूर्व प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश लम्बे समय से काफी संवेदनशील प्रदेश रहा है। भौगोलिक ही नहीं,

धार्मिक, राजनीतिक आधार पर भी यह प्रदेश आज़ादी के बाद से ही तमाम समस्याओं से जूझता रहा है।

यूपी वासी आए दिन अपराधियों और उनके सरगनाओं के बीच गैंगवार, संगठित अपराध और सामुदायिक टकराव, नेपाल बॉर्डर से सटे सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ और तस्करी, नक्सल क्षेत्र और आतंकी घटनाओं से खुद को असुरक्षित महसूस करते रहे हैं। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन इन तमाम समस्याओं से निजात मिलना तभी संभव था जब राज्य में विशेष सुरक्षा प्रणाली लाई जाए जो आम जनता के हित में काम करे और उनके भरोसे पर खरा उतरे।

क़ानून-व्यवस्था की बदहाली का शिकार रहे इस राज्य में ज्यादातर सरकारें ऐसी आईं जो अपने हितों को देखते हुए अपराधियों का धरपकड़ करती रहीं। लेकिन आम जनता के ऊपर हो रहे अन्याय को थामने का जिम्मा किसी

सरकार ने नहीं लिया।

क्राइम रोकने के नाम पर धर्म-जाति के नाम लिए जाते रहे। संगठित अपराधियों और गुंडों का अपराध उनकी जाति के आधार पर तय किया जाना आम बात थी। जो जितना बड़ा क्रिमिनल था उसे राजनीतिक पार्टियों ने उतना अधिक संरक्षण दिया। यूपी में गुंडाराज अपने पीक पर था जबकि जनता हताश निराश थी।

ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा के चुनावी एजेंडे में जाति और धर्म से परे प्रदेश की कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखा गया तो लोगों ने योगी सरकार पर भरोसा किया। इतने बड़े जनमानस के भरोसे को योगी आदित्यनाथ ने स्वीकारा और प्रदेश का मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर सबसे पहले यहां की पुलिस व्यवस्था में सुधार की ठानी।

तमाम तरह की मीटिंग की गई और विशेषज्ञों से राय ली जाती रही। सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए कई सुझावों पर अमल किया गया। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के शुरूआती दिनों में ही प्रदेश में आपराधिक घटनाओं और अपराधियों पर कार्रवाई शुरू की, जिससे अपराध जगत में हड़कंप मचने लगा।

सूबे में अपराधियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर आम बात हो गई। अपराध जगत में यूपी पुलिस और योगी सरकार का भय कायम

योगी सरकार के कार्यों की बात करने से पूर्व प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश लम्बे समय से काफी संवेदनशील प्रदेश रहा है। भौगोलिक ही नहीं, धार्मिक, राजनीतिक आधार पर भी यह प्रदेश आजादी के बाद से ही तमाम समस्याओं से जूझता रहा है।

हुआ। कहा जा सकता है कि इस तरह अपराधियों पर नकेल कसने में योगी सरकार काफी हद तक कामयाब रही जिसमें जनता का भी पूरा समर्थन उसे मिलता रहा।

राज्य में अपराधमुक्त समाज बनाने और अनुशासन कायम रखने के लिए यह बहुत आवश्यक था कि सूबे के संगठित अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण समाप्त हो, आतंकी वारदातों से निपटने के लिए खुफिया तंत्र दुरुस्त हो। साथ ही, सांप्रदायिक दंगे व तनाव को दूर करने के लिए केंद्र के साथ बेहतर समन्वय हो जिससे प्रदेश में आंतरिक शांति कायम हों।

इन्हीं बिंदुओं को अपनाते हुए योगी सरकार ने कई स्तरों पर काम किया। इसके तहत प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और

प्रगतिशील बनाने की दिशा में अनेक नए कदम उठाए गए जबकि कई कार्य अब भी जारी हैं।

उदाहरण के तौर पर कुछ महीने पहले सरकार ने स्मार्ट पुलिसिंग और पुलिस सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लखनऊ व नोएडा में कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की। दरअसल इन शहरों में बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां होने की वजह से अन्य राज्यों से लाखों लोग आते हैं। ऐसे में इन बड़े शहरों की सुरक्षा के मानकों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है जो कई मायनों में चुनौतिपूर्ण होते हैं।

ऐसे में इन शहरों को कमिश्नर प्रणाली की निगरानी मिलने से यहां की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को एकीकृत रूप में संभालने में आसानी हुई है। इसी प्रकार योगी सरकार ने पुलिस व्यवस्था की पारंपरिक प्रणाली में भी कई बदलाव किए, जिससे पुलिस सुधार की दिशा में

ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा के चुनावी एजेंडे में जाति और धर्म से परे प्रदेश की कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखा गया तो लोगों ने योगी सरकार पर भरोसा किया। इतने बड़े जनमानस के भरोसे को योगी आदित्यनाथ ने स्वीकारा और प्रदेश का मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर सबसे पहले यहां की पुलिस व्यवस्था में सुधार की ठानी।

प्रगतिशील तरीकों को अपनाया जा सके।

कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल में भी यूपी पुलिस के कार्य सराहनीय हैं। यही नहीं, जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो और संगठित अपराध सूचना प्रणाली के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी जारी है।

खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए सभी विशेष बलों और पुलिस इकाइयों के साथ व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। योगी सरकार द्वारा यूपीएसएसएफ का गठन और पुलिस व्यवस्था में सुधार एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए।

किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था, नागरिक प्रशासन और नागरिकों में सुरक्षा का माहौल आदि पुलिस बल से ही संभव होता है। इसका प्रभाव प्रदेश के आर्थिक विकास, शांति, साक्षरता और समृद्धि पर सीधे तौर पर देखने को मिलता है। जब कानून व्यवस्था का कड़ाई से क्रियान्वयन किया जाता है, तभी नागरिकों का राज्य सरकार पर भरोसा बढ़ता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार सुधारों के क्रम में तेजी से कदम बढ़ा रही है, जिसे अन्य राज्यों को भी सीख के तौर पर अपनाना चाहिए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

